R.C.-24
युवा वर्ग के विकास में कौशल विकास मिशन एवं मेक इन इण्डिया कार्यक्रम की भूमिकाः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन।

रवि भारती
O/SM-0312017
शोध छात्र, स्नाकोत्तर समाजशास्त्र विभाग
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

भूमिका :–

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) भारत सरकार की एक योजना है जो कौशल को मान्यता प्रदान करता है। यह कौशल का मानकीकरण करता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत की युवा पीढ़ी के लिए एक नई पहल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस देशके प्रत्येक युवक को आर्थिक रूप से अपने पैर पर खड़ा करने के लिए इस रोजगार योजना को आरम्भ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रोत्साहित करना है तथा बेरोजगार लोगों के कौशल विकास को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री के अनुसार ''स्किलिंग'' से एक बेहतर भारत का निर्माण हो सकता है। हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कौशल विकास हमारा मिशन हो।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रोजगार का द्वार खोलेगी। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (National Skill Development Agency, NSDA) द्वारा युवाओं को तकनीकी ज्ञान दिया जायेगा ताकि उन्हे रोजगार उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार का यह फैसला है कि तकनीकी रोजगार को बढ़ावा दिया जाय। इसके लिए रोजगारोन्मुखी स्किल ट्रेनिंग शुरू की जाय। अर्थात् सरकार यह चाहती है कि पहले तकनीकी ज्ञान के लिए ट्रेनिंग दी जाय और बाद में रोजगार देने का काम किया जाय। इसे ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अर्थात् PMKVY का नाम दिया गया है।

देश की बदलती जनसंख्यिकीय प्रोफाइल (Demographic Profile) को देखा जाये तो यह बात सामने आती है कि 54% लोग 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। अर्थात् भारत युवाओं का देश है। इनकी आकांक्षा बेहतर रोजगार की है नियोक्ताओं की अपेक्षाओं में भी दिन–प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है अतः यहाँ अच्छी तरह से प्रशिक्षित लोगों की मांग है। जनसांख्यिकीय लाभांस का लाभ लेने के लिए कौशल विकास के प्रयासों के समन्वय की जरूरत को पहचाना गया। भारत सरकार ने 31 जुलाई 2014 को कौशल विकास विभाग और उद्यमिता (Skill Development and

Entrepreneurship) के गठन को अधिसूचित किया। इसे 9 नवम्बर 2014 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship; MSDE) का एक पूर्ण मंत्रालय बना दिया गया। 16 जुलाई 2015 से यह योजना कार्य करने लगी। इस कार्य के लिए सम्बंधित पक्षों के साथ समन्वय बनाने, कुशल जन शान्ति तैयार करना, मांग एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कार्य करना, मौजूदा कौशल का मानचित्र, बाजार अनुसंधान, प्रशिक्षण पाढ्यक्रम तैयार करना, उद्योग–संस्थान Linkage, Skilling में PPP तत्व लाने, अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए व्यापक नीतियां बनाने, Soft Skills के लिए नीतिया बनाने, कम्प्यूटर शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान Industrial Training Institute (ITIS) और युवाओं के उद्यमिता शिक्षा के विस्तार से सम्बंधित कार्य के लिए जिम्मेदार बनाया गया।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम National Skill Development Corporation (NSDC), अपनी तरह का एक मात्र सार्वजनिक निजी भागीदारी है। इसका उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का व्यापक निर्माण एवं गुणवत्ता के लिए उत्प्रेरित करना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training) के लिए धन उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance), सूचना प्रणाली के रूप में, समर्थन व्यवस्था (Support System) को सक्षम बनाता है। प्रशिक्षण अकादमियों (Trainer Academies) को सीधे या भागीदारी के माध्यम से प्रशिक्षित करता है।

कौशल प्रमाणीकरण और पुरस्कार योजना का उद्देश्य, युवाओं की एक बड़ी संख्या को, कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए जुटाना और अपनी आजीविका कमाने के लिए सक्षम बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व वाली कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय को मंजूरी दी। वह है – एक करोड़ युवाओं को (2016-2020) प्रशिक्षित करना।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सरकार की गरीबी के खिलाफ एक जंग हैं और भारत का प्रत्येक गरीब और वंचित युवा इस जंग का सिपाही है। इस योजना की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को अन्तर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर की थी। साथ ही इस योजना का लोगों (प्रतीक चिन्ह) और टैगलाइन का अनावरण भी किया था।

मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों को शुरू किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम भारत में कौशल विकास योजना कार्यक्रमों की शुरूआत है। 'कौशल भारत कुशल भारत' की योजना भी इसी

का एक भाग है। 'स्किल इंडिया मिशन' योजना के अर्न्तगत चार अन्य योजनाओं (राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना) को सम्मिलित करके शुरू की गयी है।

देश को विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को पूरे भारत में लगभग 40 करोड़ भारतीयों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 2022 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 'कुशल भारत—कौशल भारत' योजना, को शुरू किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगो को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके उनकी कार्यक्षमता को बढ़ावा देना है। मुख्य रूप से कौशल विकास योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं को कौशल के विकास के लिए उन क्षेत्रों में अवसर प्रदान करना है जो कई वर्षो से अविकसित है। इसके साथ ही साथ विकास करने के नये क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें विकसित करने के प्रयास करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शब्दो में, 'कौशल विकास योजना' केवल जेब में रूपये भरना नही हैं, बल्कि गरीबों के जीवन को आत्मविश्वास से भरना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान दो प्रेरक बल हैं। वर्तमान वैश्विक माहौल में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौती से निपटने में वे देश आगे हैं जिन्होने कौशल का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। किसी भी देश में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से युवाओं पर ही जोर होता है। इस मामले में हमारा देश अच्छी स्थिति में है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उत्पादक आयु समूह में है। यह भारत को सुनहरा अवसर प्रदान करता है, परंतु एक बड़ी चुनौती भी पेश करता है।

हमारी अर्थव्यवस्था को इसका लाभ तभी मिलेगा जब हमारी जनसंख्या विशेषकर युवा स्वस्थ, शिक्षित और कुशल होगी।

भारत के पास एक अतुलनीय युवा जनसंख्या है जिससे आनेवाले समय में सामाजिक आर्थिक विकास को जोरदार बढ़वा मिलना तय है। हमारे पास 60.5 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करके ये युवा परिवर्तन के प्रतिनिधि हो सकते हैं। वे न केवल अपने जीवन को प्रभावित करने के काबिल होंगे बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकें।

हाल में ही मंजूर की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण

और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण के अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है।

नवगठित कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) और उद्योग द्वारा तय मानदंडो पर आधारित होगा कार्यक्रम के तहत तृतीय पक्ष आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षुओं को नकद पारितोषिक दी जाएगी। नकद पारितोषिक औसतन 8000 रूपए प्रति प्रशिक्षु होगी।

कौशल प्रशिक्षण (NSDC) द्वारा हाल मे ही संचालित कौशल अंतर अध्ययनों के जरिए मांग के आकलन के आधार पर दिया जाऐगा। केन्द्र और राज्य सरकारो उद्योग और व्यावसायिक घरानों से विचार विमर्श कर भविष्य की मांग का आकलन किया जाएगा। कौशल विकास के लक्ष्य निर्धारित करते समय हाल में ही लागू किये गये प्रमुख कार्यक्रम जैसे कि 'मेक इन इंडिया' डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय और ऊर्जा मिशन और स्वच्छ भारत अभियान के मांगो को भी ध्यान में रखा गया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर जोर होगा और विशेषकर कक्षा 10 व 12 के दौरान स्कूल छोड़ गये छात्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन (NSDC) के प्रशिक्षण साझेदारों द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में लगभग 2300 केन्द्रों के (NSDC) के 187 प्रशिक्षण साझेदार हैं। इनके अलावा केन्द्र एवं राज्य सरकारों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदाताओं को इस योजना के लिए योग्य होने के लिए एक जाँच प्रक्रिया से गुजरना होगा। PMKVY के तहत सेक्टर कौशल परिषद् व राज्य सरकारें भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे।

योजना के तहत एक कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (SDMS) भी तैयार की जाएगी जो सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के विवरणों और प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम की जाँच करेगी और उन्हें दर्ज भी करेगी। जहाँ तक संभव होगा प्रशिक्षण प्रक्रिया में वायोमिट्रिक सिस्टम व वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल की जाएगी जो PMKVY से जानकारी ली जाएगी जो PMKVY की प्रभावशीलता का मूल्यांकन का मुख्य आधार होंगे। शिकायतों के निपटान के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण मंत्र भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार के लिए एक ऑनलाइन नागरिक पोर्टल भी शुरू की जाएगी।

कौशल व उद्‌यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। नवगठित कौशल व उद्यम विकास मंत्रालय की 'मेक इन इंडिया' अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अभियान भारत की एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए अहम् पहल है। विकासशील अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र समेत सभी क्षेत्रों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने में इस मंत्रालय की अहम् भूमिका है। इस दिशा में उठाये गए सभी उपायों को शामिल करने के लिए एक नयी राष्ट्रीय कौशल व उद्‌यम विकास नीति भी तैयार की गयी है। इस नीति के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल के साथ विकास को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस दिशा में प्रयास मिशन के तौर पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत तीन संस्थान कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास प्रयासों को नीतिगत दिशा दे रही है और इनकी समीक्षा भी कर रही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय प्रधानमंत्री की परिषद् के नियमों को लागू करने के लिए रणनीतियों पर कार्य कर रहा है।

भारत ने विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना ली है। उम्मीद है कि भारत शीघ्र ही विश्व की तीन सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। वर्ष 2020 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केन्द्र भी बन जाएगा। जनसंख्या के सकारात्मक कारकों और उच्च गुणवत्ता वाले कार्य बल की सतत् उपलब्धता की मदद से हमारा देश विश्व अर्थव्यवस्था में विशेष छाप छोड़ सकता है।

भविष्य के बाजारों के लिए कौशल विकास से लेकर मानव संसाधन विकसित करने के लिए हाल में ही घोषित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अवश्य ही हमारी अर्थव्यवस्था को पूर्ण लाभ मिलेगा। नई नीति के तहत मिशन के तौर पर लागू की गई यह योजना मानव संसाधन और उद्‌योग के विकास में एक नए युग की शुरूआत करेगी।

<u>योजना का उद्देश्य :–</u>

इस योजना का उद्देश्य युवाओं के लिए चलाये जा रहे अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम (approved training programs) के सफल समापन पर मौद्रिक पुरस्कार (Money rewards) प्रदान कर कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। विशेष रूप से इस योजना का उद्देश्य :–

* प्रमाणीकरण की प्रक्रिया (Certificate Process) में standardization को प्रोत्साहित करना और कौशल की एक रजिस्ट्री बनाने की प्रक्रिया शुरू करना।
* भारतीय युवाओं के एक बड़ी संख्या कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए जुटाना और अपनी आजीविका का कमाने के लिए सक्षम बनाना।
* कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार और युवाओं की उत्पादकता को बढ़ाना और देशकी जरूरतों के लिए प्रशिक्षण (Training) और प्रमाण (Certification) करना।
* कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार और युवाओं की उत्पादकता को बढावा देने के लिए उन्हें कौशल प्रभाणन (Skill Certificate) के लिए मौद्रिक पुरस्कार (Monetary rewards) प्रदान कर प्रोत्साहित करना।
* पुरस्कार उम्मीदवार 8000 रू० के औसत मौद्रिक इनाम के साथ अधिकृत संस्थाओं द्वारा कौशल प्रशिक्षण लेते हैं।
* 1,500 करोड़ रूपए की अनुमानित कुल लागत में 24 लाख युवाओं को फायदा होगा।
* इस मिशन का उद्देश्य विश्व स्तर पर भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में बदलाना और 2022 तक देश की जीडीपी में 25 प्रतिशत की बढोतरी करना है।

समग्र एवं निदर्श :– अध्ययन के समग्र के अन्तर्गत गया जिला का चयन किया गया है। गया जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले युवाओं को समग्र के अन्तर्गत शामिल किया गया है। सामाजिक अनुसंधान को तथ्यमूलक और तर्कसंगत बनाने में प्रतिचयन प्रणाली एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में स्वीकार की गई है। वर्तमान अध्ययन के निदर्श के रूप में गया जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले युवाओं के समग्र में से 200 उत्तरदाताओं का उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति की सहायता से चयन कर अध्ययन सम्पादित किया गया है। संकलित तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :–

1. जनसंख्यिकीय लाभांश का पूर्ण लाभ उठाने में कौशल विकास मिशन की भूमिका की जानकारी प्राप्त करना अध्ययन का उद्देश्य है।
2. मेक इन इण्डिया कार्यक्रम युवाओं को रोजगार प्रदान करने एवं उधमशीलता को बढ़ावा देने में कितनी कारगर है। इस सम्बन्ध में सूचनादाताओं के विचार जानना।
3. युवाओं के आजीविका की पूर्त्ति में कौशल विकास मिशन की भूमिका का पता लगाना।
4. समाजिक उधमशीलता को बढाने में सरकार की भूमिका का पता लगाना।

5. युवाओं के हुनर के विकास में उपलब्धता, सरकारी संसाधनों की स्थिति एवं समस्याओं का पता लगाना।
6. सामाजिक उधमशीलता को बढ़ावा देश की बुनियादी समस्याओं का हल ढूँढा जा सकता है। इस सम्बन्ध में लोगों के विचार जानना।
7. समाजिक उधमशीलता एंव कौशल विकास योजना रोजगार और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। इस सम्बन्ध में लोगों के विचार जानना अध्ययन का उद्देश्य है।

निष्कर्ष

देश में करीब 60 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के है। रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल विकास प्राप्त करके ये युवा परिवर्तन के प्रतिनिधि हो सकते है। वे ने केवल अपने जीवन को प्रभावित करने के काबिल होंगे बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरूआत की है। इसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरूआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की बेरोजगारी की समस्या को खत्म करके देश को बेरोजगार मुक्त करने की है जिससे देश की प्रगति हो सके। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को अन्तर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर की थी।

PMKVY युवाओं के कौशल के लिए एक प्रमुख योजना है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है।

इस मिशन का उद्देश्य विश्व स्तर पर भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में बदलना और 2022 तक देश की जीडीपी में 25 प्रतिशत की बढोतरी करना है संकलित तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 61.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को रोजगार पाने के लायक बनाता है।

अतः जनसंख्यिकीय लाभांश का पूर्ण लाभ उठाने में कौशल विकास मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 67.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि कौशल विकास योजना युवओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रही है। 71.0 प्रतिशत उत्तरदाता इस प्रश्न से सहमत है कि कुशल युवा प्रोग्राम में सहभागियों की संख्या बढ़ी है।

विशाल आबादी के दबाव में भारत में रोजगार के मायने बदल रहे है। आबादी के अनुरूप नौकरी सृजन करना आसान नहीं। इससे मुकाबला करने के लिए सरकार ने कौशल विकास का प्रशिक्षण और उधमशीलता को बढ़ावा देकर स्वरोजगार की संभावना बढ़ाने का ठोस वैकल्पिक मार्ग अपनाया है। ऐसा करके नौकरी के लिए भटकते ंयुवाओं को नौकरी का सृजनकर्ता बनाने का आह्वान किया गया है।

प्रस्तुत शोध द्वारा प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि उद्यमिता एवं कौशल विकास से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और कौशल विकास से बेरोजगारी कम होगी। स्किल डेवलपमेंट से ही रोजगारी का समाधान होगा। जनसंख्यकीय लाभांश का पूर्ण लाभ उठाने में कौशल विकास मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तकनीकी संस्थानों में शिक्षण के साथ–साथ कौशल विकास पर विशेष जोर देना चाहिए क्योंकि स्वावलंबन शिक्षा एवं भविष्य में जीवनयापन के लिए किसी एक क्षेत्र में कौशल विकास उसे बेरोजगारी की पंक्ति में खड़ा नहीं कर पायेगा। कौशल विकास युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रही है, इसे उत्तरदाताओं में स्वीकार किया है साथ ही PMKVY युवाओं में हुनर का विकास करता है।

सुझाव :–

कौशल विकास अभियान की सफल में एक बड़ी चुनौती आर्थिक विकास में भौगोलिक असमानता है। केरल जैसे विकसित और शिक्षित बाजार में जहाँ कुशल श्रमिकों की बहुलता है, वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में अकुशल श्रमिक बहुतायत में मौजूद है। इसके कारण कौशल विकास कार्यक्रम में जहां केरल जैसे राज्यों में एक जैसे युवाओं की बहुलता होगी कि दोनों ही तरह के राज्यों में कौशल विकास के बाद युवाओं की जो फौज निकलेगी, वह समस्या को और बढ़ाएगी। कौशल विकास अभियान को भी भ्रष्टाचार के दीमक से बचाने की जरूरत है।

बस जरूरत है इस को लालपीताशाही से बचाने की।

अन्त में, कौशल विकास अभियान की सफलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व बैंक ने भारत में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 25 करोड़ डॉलर का कर्ज मंजूर किया है। इससे युवाओ ंको अधिक कुशल बनाया जा सकेगा, जिससे उन्हें रोजगार पाने में आसानी होगी।

संदर्भ :–

1. आलोक कुमार, योजना, मार्च 2017
2. भुवन भास्कर, कुरूक्षेत्र, अगस्त, 2016
3. हिन्दुस्तान, पटना , 27 जून, 2017
4. Scheme Document or Pradhan Mantri Kausal vikas yojana, pmkvyofficial.org.
5. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna pmkvyofficial.org 04-12-2015
6 Skillindia.gov.in
7. Business standard, 26 July, 2016
8. Ibid
9. Finnancial Express, 13 July, 2016
10. सुश्री अर्चना दत्ता–स्वतंत्र लेखिका पूर्वमहानिदेशक, डीडी न्यूज, महानिदेशक, एनएसडी (एआईआर)
11. Karl Pearson - The Grammar of science, P.10
12. Stuart Chase-The proper study of mankind. 1956, P.6.
13. Goode& Hatt-Method in social Research, Newyork, 1952, P.129
14. P.V. young-Scientific social survey and Research, Asia Publishing House, Bombay, 1960, P-302